

Mrs. Suneeta Nirankari

(Asst. Professor)

Semester- IV

Subject- History Of Modern India

(1857 A.D.- 1950 A.D)

College Name:- Indira Gandhi Government P.G. College
Bangarmau (Unnao)

आधुनिक भारत का इतिहास (1857-1950): विस्तृत अध्ययन सामग्री

I: लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन - दो विपरीत विचारधाराएँ

इस कालखंड में ब्रिटिश शासन के दो अलग चेहरे देखने को मिलते हैं।

लॉर्ड लिटन (प्रतिक्रियावादी शासन):

वर्नाकुलर प्रेस एक्ट (1878): इसे 'मुंह बंद करने वाला कानून' कहा गया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को कुचलना था क्योंकि वे ब्रिटिश नीतियों की आलोचना कर रहे थे। 'अमृत बाजार पत्रिका' रातों-रात अंग्रेजी में बदल गई थी।

भारतीय शस्त्र अधिनियम (1878): भारतीयों को बिना लाइसेंस हथियार रखना प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि गोरों के लिए यह अनिवार्य नहीं था। यह नस्लीय भेदभाव का चरम था।

सिविल सेवा आयु: इन्होंने भारतीयों को हतोत्साहित करने के लिए परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी।

लॉर्ड रिपन (उदारवादी शासन):

स्थानीय स्वशासन का जनक: इन्होंने 1882 में प्रस्ताव पारित कर स्थानीय बोर्डों और नगरपालिकाओं की स्थापना की ताकि भारतीयों को प्रशासन की शिक्षा मिले।

इल्बर्ट बिल विवाद (1883): रिपन चाहते थे कि भारतीय जज यूरोपीय अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई करें। अंग्रेजों ने इसका इतना विरोध किया कि रिपन को कानून बदलना पड़ा। इससे भारतीयों ने सीखा कि संगठित होकर विरोध कैसे किया जाता है।

II: लॉर्ड कर्जन और बंगाल का विभाजन (1905)

कर्जन की मंशा: अधिकारिक तौर पर कारण 'प्रशासनिक असुविधा' बताया गया, लेकिन असली मकसद हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ना और बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था।

विभाजन का स्वरूप: पश्चिमी बंगाल (हिंदू बहुल) और पूर्वी बंगाल व असम (मुस्लिम बहुल)।

स्वदेशी आंदोलन: यह पहला बड़ा जन आंदोलन बना। इसमें 'आत्मशक्ति' पर जोर दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और स्वदेशी उद्योगों (जैसे बंगाल केमिकल्स) की स्थापना हुई।

III: कृषि का व्यवसायीकरण और इसके घातक प्रभाव

व्यवसायीकरण का अर्थ: बाजार के लिए फसलें उगाना, न कि परिवार के उपभोग के लिए।

ब्रिटिश लाभ: ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल (कपास, जूट) की जरूरत थी। साथ ही चीन के साथ व्यापार के लिए अफीम और चाय की खेती कराई गई।

खाद्यान्न का अभाव: किसान अनाज के बजाय नकदी फसलें उगाने लगे, जिससे देश में अकाल की बारंबारता बढ़ गई (जैसे 1943 का बंगाल का अकाल)।

गरीबी: नकदी फसलों की खेती महंगी थी, जिसके लिए किसानों ने ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया और अंततः अपनी जमीन से हाथ धो बैठे।

IV: रेलवे का विकास - औपनिवेशिक हित बनाम राष्ट्रीय लाभ

रेलवे का जाल: डलहौजी ने सैन्य और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इसे शुरू किया।

आर्थिक ड्रेन (Wealth Drain): रेलवे के निर्माण में लगी सारी सामग्री ब्रिटेन से मंगवाई गई। भारतीय करदाताओं का पैसा 'मुनाफे की गारंटी' के रूप में ब्रिटिश निवेशकों को दिया गया।

सकारात्मक पहलू: रेलवे ने भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ा। महात्मा गांधी ने बाद में इसी रेलवे का उपयोग कर पूरे भारत में अपनी विचारधारा का प्रसार किया।

V: शिक्षा का विकास - मैकाले से सार्जेंट योजना तक

मैकाले मिनट (1835): इन्होंने भारतीय संस्कृति को 'निम्न' बताया और अंग्रेजी को अनिवार्य किया ताकि ब्रिटिश प्रशासन के लिए सस्ते 'बाबू' मिल सकें।

वुड्स डिस्पैच (1854): इसे शिक्षा का आधार स्तंभ माना जाता है। इसने प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में देने की सिफारिश की।

प्रभाव: हालांकि शिक्षा का लक्ष्य क्लर्क बनाना था, लेकिन पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से परिचित कराया।

VI: संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण चरण

1909 का अधिनियम: पहली बार 'सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व' (Separate Electorate) दिया गया। लॉर्ड मिंटो को 'सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक' कहा गया।

1919 का अधिनियम: 'द्वैध शासन' (Diarchy) का प्रयोग। विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' में बांटा गया।

1935 का अधिनियम: यह भारत के वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट है। इसमें केंद्र में द्वैध शासन और राज्यों में स्वायत्तता दी गई। इसमें 'फेडरल कोर्ट' की भी स्थापना हुई।

VII: सांप्रदायिकता का उदय (Rise of Communalism)

चरण 1: 1857 के बाद अंग्रेजों ने महसूस किया कि हिंदू-मुस्लिम एकता उनके लिए खतरा है।

चरण 2: मुस्लिम लीग (1906) का गठन और अंग्रेजों द्वारा उसे प्रोत्साहन।

चरण 3: जिन्ना का उदय और 1940 का लाहौर प्रस्ताव, जिसने साफ कर दिया कि मुस्लिम लीग अब केवल एक अलग राष्ट्र (पाकिस्तान) चाहती है।

VIII: स्वतंत्र भारत का एकीकरण और सरदार पटेल

विकट स्थिति: 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ लेकिन खंडित होने की कगार पर था।

रियासती विभाग: सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने राजाओं को 'प्रिंसी पर्स' (पेंशन) और सम्मान का लालच देकर भारत में शामिल होने के लिए मनाया।

तीन बड़ी चुनौतियाँ: * जूनागढ़: नवाब पाकिस्तान भाग गया, जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय।

हैदराबाद: निज़ाम के 'रजाकारों' ने अत्याचार किए, जिसके बाद 'ऑपरेशन पोलो' के तहत सेना भेजी गई।

कश्मीर: पाकिस्तान समर्थित आक्रमण के बाद महाराजा ने भारत के साथ 'विलय पत्र' पर हस्ताक्षर किए।